भारत सरकार

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.683

बुधवार, दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

महाराष्ट्र में आदर्श सौर गाँव

683. डॉ. बच्छाव शोभा दिनेश:

क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र राज्य, विशेषकर धुले और नासिक जिलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना (पीएम-एसजीएमबीवाई) के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पीएम-एसजीएमबीवाई के घटक-बी के अंतर्गत सभी आदर्श सौर गांवों का, विशेषकर महाराष्ट्र में, जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को महाराष्ट्र सरकार या किसी संसद सदस्य से इसके लिए कोई प्रस्ताव/अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क): पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी: एमबीवाई) रूफटॉप सौर (आरटीएस) प्रणालियों की स्थापना के लिए एक मांग आधारित योजना है, जिसमें देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड कनेक्टेड बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं।

महाराष्ट्र राज्य में, दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर कुल 5,17,763 आवेदन प्राप्त हुए हैं और कुल 3,54,687 आरटीएस प्रणालियां लगाई गई हैं, जिससे 5,66,932 परिवार लाभान्वित हुए हैं। धुले तथा नासिक जिले के संबंध में विवरण निम्नानुसार है:

जिला	आवेदन की संख्या	आरटीएस स्थापनाएं	लाभान्वित परिवार
धुले	14,445	10,821	10,984
नासिक	32,492	22,503	41,994

(ख) से (घ): पीएमएसजी:एमबीवाई का एक घटक देश के प्रत्येक जिले में मॉडल सौर गांव विकसित करना है। इस घटक के लिए 1 करोड़ रु. प्रति मॉडल गांव की केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के प्रावधान के साथ 800 करोड़ रु. की राशि आवंटित की गई है। मॉडल सौर गांव के रूप में विकसित होने वाले गांव का चयन चैलेंज मोड पर आधारित है। पीएमएसजी:एमबीवाई के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन एजेंसी-आरईसी लि. ने सूचित किया है कि दिनांक 28.11.2025 की स्थिति के अनुसार, चैलेंज मोड 390 जिलों में पूरा किया गया, जिसमें से 174 जिलों ने मॉडल सौर गांवों के रूप में विकसित किए जाने वाले गांवों का चयन कर लिया है।

महाराष्ट्र राज्य द्वारा उसके किसी भी जिले में मॉडल सौर गांव के विकास के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अभी प्रस्तुत की जानी है।

****